रोज़ी रोटी अधिकार अभियान दिल्ली

11 अगस्त 2011 के लिए प्रैस नोट

दिल्ली के गरीबों की आवाज! हमें पैसे नहीं, हमें चाहिए अनाज!!

हमें खाद्य सुरक्षा दो, राशन व्यवस्था मज़बूत करो

मीडिया तथा नीतिगत हलकों में इस बात को लेकर काफी चर्चा है कि सरकार जन वितरण प्रणाली के स्थान पर प्रत्यक्ष नकद सब्सिडी लाना चाहती है। इस दिशा में सरकार ने पहला कदम अपने बजट घोषणा में यह कह कर करदी कि वे उर्वरक और मिट्टी के तेल पर दी जाने वाली सब्सिडी के स्थान पर नकद हस्तांतरण करेगी। खाद्य सुरक्ष कानून का मसौदा जो मंत्रियों के सशक्त समूह द्वारा अनुमोदित किया गया है उस में भी राशन व्यवस्था (पी डी एस) के सुधार के लिए प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण का उल्लेख है। नंदन नीलकेनी की अध्यक्षता में बनी समिति को भी ऐसी पद्धति तलाशने को कहा गया है जहाँ राशन व्यवस्था (पीडीएस) के स्थान पर प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण हो सके।

हाल ही में दिल्ली सरकार राशन व्यवस्था (पीडीएस) को समाप्त कर प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण लाने का प्रयास किया है। इसके तहत योग्य लागों को उनके बैंक खाते में एक निश्चित् मासिक राशि दी जाएगी जिसे वे अपनी इच्छानुसार खर्च कर सकेगें। सरकार ये तर्क दे रही है कि इससे लीकेज कम होगा और उसका वित्तीय बोझ भी कम होगा। **सेवा** तथा **इंडिया डेवलपमेंट फाउण्डेसन** के साथ मिलकर दिल्ली सरकार ने **यू एन डी पी** की वित्तीय सहायता से रघुवीर नगर में 100 परिवारों पर इस पायलॉट परियोजना को चला रही है। इसके तहत इन 100 परिवारों को राशन के बदले प्रति माह रू1,000 दिये जाएगें। इसके अतिरिक्त 400 परिवारों का सर्वे "नियंत्रण समूह"(control group) के रूप में किया गया है। इस पायलॉट परियोजना का परिणाम आना अभी बाकी है।

रघुवीर नगर दिल्ली के गरीब इलाकों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, इसके साथ ही अध्ययन में शामिल 100 परिवार जिन्हे पैसे दिए जा रहे हैं उन्होंने भी राशन लेने की इच्छा जताई है। इस प्रकार उनके राय की अंदेखी की गई है। इसका सेम्पल साईज़ इतना छोटा है कि पूरे राज्य की नीति परिर्वतन के लिए अपर्याप्त है। इसके अतिरिक्त इसमें पहचान की भी समस्या है और ये स्पष्ट नहीं है कि जिस बी पी एल कार्डधारी को इस में शामिल किया गया है वह वास्तव में गरीब है। एन एस एस के 2004–05 के अंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में गरीबी रेखा से नीचे(उपभोग और व्यय के आधार पर) रहने वाले सिर्फ 27. 5% लोगों के पास ही बीपीएल कार्ड है।

रोज़ी रोटी अधिकार अभियान दिल्ली सरकार द्वारा राशन व्यवस्था को समाप्त करने की इस परियोजना का पुरज़ोर विरोध करती है। हमें यह दृढ़ विश्वास है कि पूरे देश और दिल्ली में भूख और कुपोषण के उच्च स्तर को देखते हुए एक मजबूत राशन व्यवस्था की जरूरत है जो रियायती कीमतों पर न्यूनतम खद्यान्न की गॉरेन्टी देता हो। प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण स्वयं ही खामियों से भरा हुआ है इससे गरीबों के छटनी या शामिल होने के पहचान की त्रुटियों का हल नहीं होगा, बढ़ती महंगाई के इस दौर में गरीबों पर ये एक और आघात होगा, इसके अतिरिक्त लिकेज इत्यादी की जो समस्यायें पी डी एस में है वह इस में भी होंगी।

सर्वेक्षण के निष्कर्ष

रोज़ी रोटी अधिकार अभियान दिल्ली ने गरीबों की प्राथमिकताएँ समझने के लिए 4005 परिवारों का सर्वेक्षण किया इसमें दिल्ली के विभिन्न झुग्गी बस्तियों, पूनर्वास कॉलोनियों एंव बेघर व्यक्तियो को शामिल किया गया था(रिपोर्ट का सारांश संलग्न है)। इस सर्वे में सभी उत्तरदाताओं में से 91.4% का कहना था कि उन्हे नकद हस्तांतरण के स्थान पर एक मजबूत राशन व्यवस्था चाहिए, **जबकि सिर्फ 5% का कहना था कि उन्हे राशन के स्थान पर नकद हस्तांतरण चाहिए** जबकि शेष उत्तरदाताओं की कोई राय नहीं थी।

रोज़ी रोटी अधिकार अभियान दिल्ली

सर्वे में यह भी पाया गया कि इन इलाकों में रहने वाले दिहाड़ी मजदूरों में से सिर्फ 31.5% के पास ही बीपीएल कार्ड था, जबकि सभी उत्तरदाताओं में से 17% के पास किसी प्रकार का कोई भी कार्ड नहीं था। उत्तरदाताओं में से 60% का कहना था कि उन्हे राशन नियमित रूप से वितरित किया जाता है और लगभग 60% का कहना था कि उन्हें जितना मिलना चाहिए उससे कम (49 किलो गेहूँ{35} और चावल{14} प्रति माह) मिलता है। कईयों को राशन नहीं मिलने का कारण था कि उनके पास राशन कार्ड नहीं थे या जो राशन कार्ड थे उन पर मुहर नहीं लगी हुई थी अथवा रद्द कर दिए गए थे या उनका नवीनीकरण या बायोमेट्रिक नहीं हुआ था। राशन दूकान बंद रहती है या दूकानदार राशन देने से मना कर देता है इस प्रकार की समस्यायें भी सामने आई।

दूसरी ओर सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि नकद आधारित कल्याणकारी योजनाएँ जैसे वृद्धा, विधवा और विकलांगता पेंशन आदि में भी कई प्रकार की समस्यायें हैं। सर्वे में पाया गया कि सिर्फ 63% को ही नियमित रूप से पेंशन की रकम मिलती है(विकलांगों के मामले में तो यह सिर्फ 30% ही था)। इसके अलावा उन्हे बैंक खाता खोलने में, दस्तावेजों में, आवेदन प्रक्रिया में और बैंक अधिकारियों के रवैये एवं बिचौलियों के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अध्ययन में पाया गया कि दिल्ली में प्रभावी राशन प्रणली के लिए राशन व्यवस्था में व्यापक सुधर की आवश्यकता है, किन्तु लोगों का कहना था कि उन्हे राशन व्यवस्था में सुधार चाहिए न कि नकद हस्तांतरण। इसके अतिरिक्त अनुभव से ये पता चला कि नकद हस्तांतरण की योजनाओं के वितरण में समस्याओं की भरमार है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बीपीएल के सर्वे का है, जिसमें मनमाने तरीके से इनकी पहचान कर कार्ड जारी किए जाते हैं, दूसरी समस्या यह है कि सरकार लोगों को बिना बताए या उचित व्यवस्था किए बिना ही लगातार नीतियों में परिवर्तन (जैसे कार्डो का स्टापिंग, बायो मेट्रिक आदि) करती रहती है जिसके परिणमस्वरूप लोग अपने अधिकार से वंचित हो जाते हैं।

दिल्ली की विभिन्न बस्तियों में हमारे हाल के अभियान एवं सर्वे के परिप्रेक्ष्य में हमारी निम्न मांगें हैं :

1. दिल्ली में राशन व्यवस्था (पीडीएस) को समाप्त करने के बजाए इसे और मजबूत करो एवं इसके अंतर्गत चावल एवं गेहूँ के साथ ही साथ दालें, चीनी, मिट्टी का तेल, खाद्य तेल एवं मोटे अनाज को भी शामिल करो।

2. यह स्पष्ट हो चुका है कि लक्षित प्रणाली असफल हो चुकी है अतः राशन व्यवस्था (पीडीएस) का सर्वव्यापीकरण करो और लोगों को विभाजित करनेवाली एपीएल/बीपीएल नीति बंद कारो।

3. राशन व्यवस्था (पीडीएस) में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाए जाएँ जिसके तहत पारदर्शिता बढ़ाना, सशक्त शिकायत निवारण प्रणाली, राशन दूकान द्वारा घर घर जा कर राशन वितरण, पूर्ण कम्पूटिरीकरण एवं राशन दूकानदारों के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही आदि।

4. राशन कार्डों के नवीनीकरण की समस्या से जुझ रहे दिल्ली वासियों की समस्या का तत्काल समाधान किया जाए।

हम ये मांग करते है कि बड़ी नीतियाँ (जैसे राशन व्यवस्था "पीडीएस" को समाप्त कर प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण लाना) बनाने से पहले इस पर व्यापक बहस हो विशेषकर उनलोगों के साथ जो सीधे तौर पर इससे प्रभावित हैं। सरकार को दिल्ली की राशन व्यवस्था मजबूत करने के लिए दिल्ली के विभिन्न बस्तियों में गरीब लोगों के साथ अवश्य विचार विमर्श करना चाहिए।

वक्ताः अंजली भरद्वाज (सतर्क नागरिक संगठन), धर्मेंद्र (लोक अधिकार), दीपा सिन्हा (जे एन यू), रशपाल कौर (एन एफ आइ डब्लू), सेहबा फारूकी (एडवा) तथा विमला(सीफार)

एपील–बीपीएल बंद करो! सबको सस्ता राशन दो!

पैसा नहीं अनाज चाहिए!!